

राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक तृतीय, जोधपुर।

.... प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती किरण पत्नी श्री पीर सिंह
2. श्री नवीन शेखावत पुत्र स्व. पीर सिंह
3. श्री संग्राम सिंह पुत्र स्व. पीर सिंह जाति राजपूत,
निवासीगण-64बी, अजीत कॉलोनी, जिला जोधपुर

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री भरत बूब

अभिभाषक

....प्रार्थी की ओर से

...अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से

निर्णय दिनांक :31.05.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर वृत्त जोधपुर (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 05.12.2014 प्रकरण संख्या 176/2013 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप पंजीयक तृतीय जोधपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा जोधपुर शहर अजीत कॉलोनी में स्थित पैतृक मकान सं 64 बी का बंटवाडा का दस्तावेज, पंजीयन हेतु दिनांक 17.01.2012 को उप पंजीयक, तृतीय जोधपुर के समक्ष पेश करने पर उप पंजीयक ने उक्त बंटवाडा की सम्पत्ति की मालियत रु 41,47,200/- पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 के अनुसार अधिकतम मुद्रांक कर व सरचार्ज रु 11,000/- एवं 1 प्रतिशत पंजीयन शुल्क रु 41,580/- अप्रार्थीपक्ष से वसूल कर मूल दस्तावेज सम्बन्धित पक्षकार को लौटा दिया गया। तत्पश्चात् पंजीयन ऑडिट के दौरान यह आक्षेप लिया गया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 42 के अनुसार विभाजन पत्र पर सम्पत्ति के एक हिस्से को छोड़कर अलग हुए हिस्सों पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान है तथा दिनांक 09.07.98 की

217

अधिसूचना नये स्टाम्प एक्ट, 2004 के शिड्यूल 42 के असंगत होने के कारण उक्त अधिसूचना विधि मान्य नहीं है। अतः एक बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्से की बाजार मालियत रु 41,47,200/- पर कन्वेन्स की दर से दिये अंतर मुद्रांक कर व सरचार्ज रु 2,17,096/- एवं पंजीयन शुल्क की राशि रु शून्य वसूली हेतु अपवंचना से आक्षेपित किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उप पंजीयक द्वारा प्रकरण वसूली हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 (5) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 व सपठित नियम 65 (2) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय द्वारा यह अवधारित किया है कि प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 के अनुसार अधिकतम 11,000/- मुद्रांक कर व सरचार्ज तथा सम्पत्ति की मालियत 41,47,200/- रु. पर 1 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क 41,580/- वसूल किये गये हैं जो विधिसम्मत है तथा इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स खारिज किया है जिसके विरुद्ध राज्य पक्ष की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 2 (xx) में विभाजन-पत्र (Partition Deed) को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल-42 के अनुसार विभाजन पत्र पर सम्पत्ति के एक सबसे बड़े हिस्से को छोड़कर शेष अलग हुये हिस्से/हिस्सों पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज के द्वारा विभाजन-पत्र के माध्यम से अचल सम्पत्ति विभिन्न बटवाराकर्ताओं के मध्य विभाजन किया गया है जिसमें सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा स्वामित्व एवं अधिकार हस्तान्तरित हुआ है। अतः उक्त आर्टिकल-42 की अनुपालना करते हुये कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है जिसके आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

5. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि दस्तावेज पंजीयन के समय उक्त अधिसूचना प्रभावी थी तथा उपपंजीयक द्वारा इसी अधिसूचना अनुसार विभाजन पत्र का पंजीयन किया गया है। अतः ऑडिट आक्षेपानुसार उपपंजीयक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

am

7. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स का मुख्य आधार यह था कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल-42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपत्ति के एक बड़े हिस्से को छोड़ते हुये शेष हिस्से की मालियत पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय होना चाहिए। अप्रार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98-52 के अनुसार पैतृक संपत्ति के बंटवारा नामा पर एक बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/- मुद्रांक कर लिये जाने की रियायत होने की बात कही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेफरेन्स इस आधार पर खारिज किया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98-52 के अनुसार पैतृक संपत्ति के बंटवारानामा पर एक बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/- मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान है।

प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नहीं तथा इसका लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 17.01.2012 पर देय है या नहीं। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :-

91. Repeal and Savings —

(2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक कि यह अधिसूचना अतिष्ठित (Superseded) न कर दी जावे। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपत्र या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है :-

am

9 - Power to reduce, remit or compound duties

(1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable. इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नहीं मानी जा सकती।

इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक : एफ 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है

जो निम्नुसार है :- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :- "राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.2(50)वित/कर/10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडप्टेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियाँ राज्य सरकार को थी तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियाँ राज्य सरकार को प्राप्त है। राज्य सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क में रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।"

202

लगातार.....5

विभाग स्वयं द्वारा ली गयी उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क में रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 17.01.2012 पर देय है।

9. प्रकरण में इस बिन्दु पर भी विचार किया जाता है कि जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वह संपत्ति पैतृक है या नहीं। पैतृक संपत्ति के संबंध में The Advanced Law Lexicon (Law Dictionary compiled and edited by P. Ramanatha Aiyar Published by Wadhwa & Company Nagpur, India 3rd Edition Reprint 2007) में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :— Ancestral Property : If property came to a son as gift from his father, it can not be regarded his ancestral property. **Ancestral properties in the ordinary sense mean property of the father which is inherited. Ancestral property does not necessarily mean property which has been a long time in a family, it rather means, property derived from the proprietor's father.** इस डिक्शनरी में पैतृक संपत्ति के संबंध में की गई व्याख्या से यह स्पष्ट है कि यदि कोई संपत्ति पिता या उच्चतर श्रेणी के पूर्वजों से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह पैतृक संपत्ति की श्रेणी में है।

बंटवारनामा दस्तावेज पंजीयन दिनांक 17.01.2012 में बंटवारनामा अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित हुआ है। दस्तावेज में श्री पीर सिंह का स्वर्गवास होना अंकित है तथा दस्तावेज में यह उल्लेख है कि दस्तावेज से संबंधित संपत्ति श्री पीर सिंह द्वारा क्रय की गई थी। जवाब के साथ प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 19.08.1975 की फोटो प्रति से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि श्री पीर सिंह द्वारा क्रय की गयी है। इस प्रकार संपत्ति श्री पीर सिंह की स्व-अर्जित संपत्ति है परन्तु अप्रार्थीगण को यह संपत्ति श्री पीर सिंह की मृत्यु के पश्चात विरासतन प्राप्त हुई है जो अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति मानी जायेगी। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है कि बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति पैतृक नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति अप्रार्थीगण को उनके पिता की मृत्यु के बाद की संपत्ति विरासतन प्राप्त होने के कारण पैतृक एवं ऐसे दस्तावेज पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 लागू होने के कारण निगरानी सारहीन है एवं खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नैथूराम)
सदस्य